एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

दिसंबर 2012
VOL. XXVI ISSUE IV

इस अंक में

6 भारत–चीन व्यापार 76 बिलियन यूस डॉलर के साथ सर्वोच्च स्तर पर
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं
8 पिछली तिमाही
9 एक्ज़िम बैंक खबरों में
10 भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी के निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीतियां
11 वित्तीय वर्ष 2013 में भारत के कृषि निर्यात में विस्तार
12 संसाधन संपन्न अफ्रीका में भारतीय निवेश
13 एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप और साहित्य समीक्षा
14 देशों का सूक्ष्मावलोकन
15 मुद्रा की प्रवृत्तियां
16 एक दशक के दौरान सेज निर्यात में 40 गुना वृद्धि

भारतीय निर्यात–आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

बढ़ते व्यापार और निवेश से भारत–आसियान संबंधों में मजबूती

लगभग एक दशक पहले शुरू हुए दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), जिसमें ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैण्ड और वियतनाम शामिल हैं, के साथ भारत की व्यापार भागीदारी में शुरूआत से ही तेजी रही. भारत वर्ष 1992 में आसियान का अंचलीय संवाद भागीदार बन गया.

भारत और आसियान के बीच गहरा होता व्यापार संबंध आंकड़ों में आई सतत तेजी में प्रतिबिम्बित होता है. आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार 2006–07 के 30.7 बिलियन यूएस डॉलर से दुगुने से अधिक बढ़कर 2011–12 में 79.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया तथा भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा. इस अवधि के दौरान जहां निर्यातों में औसतन 23.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, वहीं आयातों में 18.6 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई. **(तालिका)**.

वर्ष 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र को भारत के निर्यात 36.6 बिलियन यूएस डॉलर के हुए, जिसमें 2010–11 के 25.6 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई. 2011–12 में भारत के वैश्विक निर्यात बाज़ार में आसियान का 12 प्रतिशत हिस्सा रहा. 2012–13 में पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल–दिसम्बर 2012) में 22.5 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ इस क्षेत्र को वार्षिक निर्यातों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

वर्ष 2011–12 में आसियान को भारत से निर्यात की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, जहाज, नाव और अन्य समरूपी संरचनाएं, जैविक रसायन, मांस और खाद्य मांस के अवशेष, मशीनरी और औजार रहे हैं **(चार्ट 1)**.

चार्ट 1 : आसियान को भारत से प्रमुख निर्यात, 2011–12

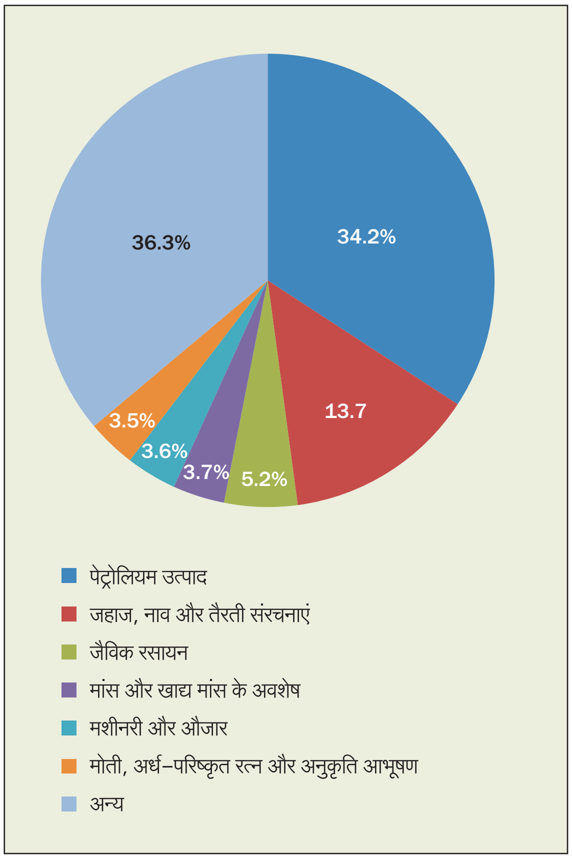

स्रोतः डीजीसीआईएस, एमओसीआई, भारत सरकार

पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए भारत का सबसे बड़ा बाज़ार सिंगापुर (2011–12 में 8.3 बिलियन यूएस डॉलर) है. अन्य बाज़ारों में इंडोनेशिया और मलेशिया हैं. वर्ष 2011–12 में भारत से जहाज, नाव और अन्य समरूपी संरचनाओं के निर्यात के लिए भी सिंगापुर सबसे बड़ा बाज़ार रहा है.

तालिका : आसियान के साथ भारत का व्यापार (बिलियन यूएस डॉलर)

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
आसियान को भारत से निर्यात	12.6	16.4	19.1	18.1	25.6	36.6
आसियान से भारत में आयात	18.1	22.7	26.2	25.8	30.6	42.6
आसियान के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार	30.7	39.1	45.3	43.9	56.2	79.2

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई), भारत सरकार

चार्ट 2: आसियान से प्रमुख आयात मदें 2011–12

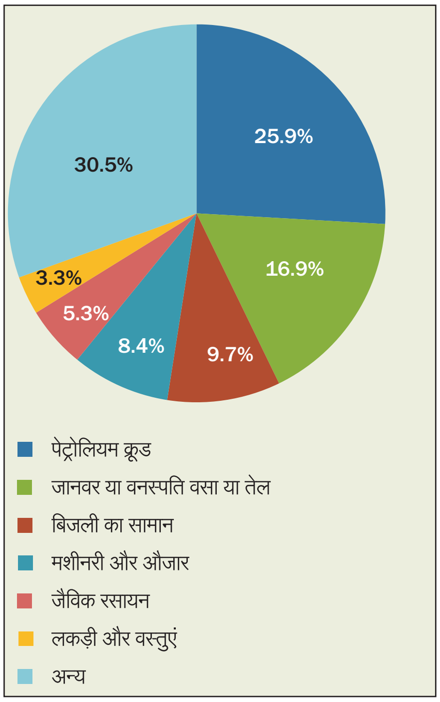

स्रोत : डीजीसीआईएस, एमओसीआई, भारत सरकार

आशियान क्षेत्र से भारतीय आयात में दुगुनी से अधिक वृद्धि हुई है और यह 2006–07 के 18.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2011–12 में 42.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. वर्ष 2011–12 में इस क्षेत्र से भारत में आयात देश के कुल आयात का लगभग 8.7 प्रतिशत हिस्सा रहा है. 2012–13 में वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में इस क्षेत्र से आयात 32.6 बिलियन यूएस डॉलर रहे हैं.

वर्ष 2011–12 में आसियान क्षेत्र से प्रमुख आयातों में अन्य के साथ–साथ पेट्रोलियम, क्रूड, जानवर या वनस्पति वसा और तेल, बिजली का सामान, मशीनरी और औजार तथा जैविक रसायन शामिल हैं **(चार्ट 2)**. भारत के लिए वनस्पति तेल का वर्तमान में सबसे बड़ा स्रोत इंडोनेशिया है. अन्य स्रोतों में मलेशिया, थाइलैण्ड और कम्बोडिया शामिल हैं. आसियान क्षेत्र से 2011–12 में पेट्रोलियम क्रूड का भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता मलेशिया है. इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई से भी क्रूड की पर्याप्त मात्रा आयात की जाती है.

विश्वभर में भारत के लिए सिंगापुर चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार और 20वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है. यह आसियान क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार और आयात के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है. दुनियाभर में भारत के लिए इंडोनेशिया 11वां सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार और 10वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है. इसके अलावा, आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे बड़ा आयात स्रोत और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है.

भारत–आसियान निवेश संबंध

अप्रैल 2000 सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान एशियाई क्षेत्र से भारत में संचयी एफडीआई कुल 19.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (भारत के कुल की 10.6 प्रतिशत) रही. भारत में वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह में मॉरिशस के बाद सिंगापुर दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा और आसियान क्षेत्र से सबसे बड़ा निवेशक रहा. आसियान देश विशेषकर सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड और इंडोनेशिया भारत में धीरे–धीरे दूरसंचार, होटल और पर्यटन सेवाएं, भारी उद्योग, रसायन, उर्वरक, वस्त्र, पेपर और लुगदी तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं.

अप्रैल 2002 से नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान आसियान क्षेत्र में भारतीय निवेश 41.1 बिलियन यूएस डॉलर हुआ. इस अवधि में भारत के कुल ओडीआई में आसियान क्षेत्र का 30.9 प्रतिशत हिस्सा रहा. इस क्षेत्र में भारत के कुल ओडीआई में 95.3 प्रतिशत हिस्से के साथ सिंगापुर सबसे बड़ा गंतव्य स्थान रहा. भारतीय कंपनियां मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, इंजीनियरिंग माल, तेल और गैस खोज, कृषि रसायन, आतिथ्य–सत्कार, उपकरण विनिर्माण आदि में लगी हुई हैं.

आसियान क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार संबंध 1991 की भारत की आर्थिक उदारीकरण नीति का परिणाम हैं. पूर्वी–एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने 1992 में 'पूर्व की ओर देखो' नीति की शुरुआत की. भारत 1992 में आसियान का अंचलीय संवाद भागीदार बना, 1995 में पूर्ण संवाद भागीदार, 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) का सदस्य और 2002 में सम्मेलन स्तरीय भागीदार (चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बराबर) बन गया. भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग (सीईसीए) के लिए ढाँचागत करार पर 2003 में हस्ताक्षर किये जो आसियान के साथ एफटीए के लिए आधार बना. सीईसीए के लिए ढांचागत करार के प्रमुख तत्वों में माल, सेवाओं और निवेश एवं निर्धारित क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग में एफटीए शामिल है. अगस्त 2009 में भारत ने थाइलैण्ड में आशियान सदस्यों के साथ माल में व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये. इस करार से दोनों क्षेत्रों के बीच 90 प्रतिशत उत्पादों पर प्रशुल्कों में कमी आएगी तथा 2016 तक 4000 से अधिक उत्पादों पर प्रशुल्कों को समाप्त करने की उम्मीद है. सेवा क्षेत्र में व्यापार में भारत ने शिक्षण, नर्सिंग, वास्तुशिल्प, चार्टर्ड एकाउंटेंसी और औषधियों सहित कई क्षेत्रों के लिए अनुरोध किया है क्योंकि इसके पास इन क्षेत्रों में अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेशनलों की बड़ी तादाद है जो आसियान क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. भारत आसियान देशों में दूरसंचार, आईटी, पर्यटन और बैंकिंग नेटवर्क को भी बढ़ाने का इच्छुक है.

आसियान–भारत एफटीए

वर्ष 2003 में दूसरे आसियान–भारत सम्मेलन में आसियान और भारत के बीच आसियान–भारत व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किये गए. इस ढांचागत करार ने आसियान–भारत क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश क्षेत्र

(आरटीआईए) की स्थापना के लिए बुनियाद रखी, जिसमें माल, सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफटीए) शामिल है.

माल के व्यापार के लिए करार

भारत सरकार और आसियान के सदस्यों ने 13 अगस्त, 2009 को व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए ढांचागत करार के अंतर्गत माल के व्यापार के लिए करार पर हस्ताक्षर किये. इसके जरिये दोनों क्षेत्र करार में वर्णित प्रशुल्क वचनबद्धताओं की अनुसूची के साथ धीरे–धीरे अपनी एमएफएन प्रशुल्क दरों का उदारीकरण करेंगे. यह करार 1 जनवरी, 2010 से लागू हो गया है. इस करार के अंतर्गत प्रशुल्कों में कटौती की वचनबद्धताओं की सूची नीचे दी गई है.

सामान्य ट्रैक में रखी गई प्रशुल्क दरों के लिए प्रयुक्त एमएफएन प्रशुल्क दरों को कम किया जायेगा और नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाद में समाप्त कर दिया जायेगाः

सामान्य ट्रैक –1 (एनटी–1)

- ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड और भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2013
- फिलीपीन्स और भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2018
- भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2013 और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2018.

सामान्य ट्रैक –2 (एनटी–2)

- ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड और भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2016
- फिलीपीन्स और भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2019
- भारत के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2016 और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के लिए 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2021.

संवेदनशील ट्रैक (एसटी)

- संवेदनशील ट्रेक में प्रशुल्क दरों के 5 प्रतिशत से अधिक प्रयुक्त एमएफएन प्रशुल्क दरों को घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा.

अनन्य सूची (ईएल)

- इस सूची में निर्धारित वचनबद्धताएं नहीं हैं लेकिन बाजार पहुँच में सुधार की दृष्टि से प्रशुल्क दरों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जायेगी.

सेवाओं में व्यापार के लिए करार और निवेश करार

दिसम्बर 2012 में भारत में नई दिल्ली में संपन्न भारत–आसियान सम्मेलन के समय भारत तथा आसियान ने सेवाओं और निवेश में एफटीए को अंतिम रूप दिया.

आसियान के प्रत्येक सदस्य को फरवरी 2013 तक सेवा एवं निवेश समझौते के लिए विधिक दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

आपसी संपर्क और व्याख्यान श्रृंखलाओं का आयोजन, युवा विनिमय कार्यक्रम, राजनयिकों और मीडिया विनिमय जैसे कार्यक्रमों के जरिये भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अकादमिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जा रहा है. दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जारी कुछ अन्य कार्यकलापों में आसियान–भारत सहयोग निधि, आसियान विकास निधि, आसियान–भारत एस एण्ड टी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) निधि और भारत–आसियान ग्रीन निधि शामिल हैं.

आसियान सम्मेलन 2012

'एक समुदाय, एक नियति' विषय पर 21वां आसियान शिखर सम्मेलन नवम्बर 2012 में नामपेन्ह में संपन्न हुआ जिसमें 10 आसियान सदस्य देशों के नेता शामिल हुए.

आसियान देशों के प्रमुखों ने आसियान चार्टर के कार्यान्वयन की प्रगति, आसियान समुदाय के लिए रोडमैप, 20वें आसियान सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई, आसियान संबंधों लिए मास्टर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान–प्रदान किया.

आसियान नेताओं ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए तथा सहमति प्रदान की :

- आसियान मानवाधिकार घोषणा को अपनाने के बारे में नामपेन्ह वक्तव्य
- आसियान मानवाधिकार घोषणा (एएचआरडी)
- आसियान क्षेत्रीय खनन कार्रवाई केन्द्र (एआरएमएसी) की स्थापना के लिए आसियान नेताओं का संयुक्त वक्तव्य
- आसियान क्षेत्रीय खनन कार्रवाई केन्द्र (एआरएमएसी) की स्थापना के लिए संकल्पना पेपर

नेताओं ने निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वीकार किया: आसियान मानवाधिकार घोषणा (एएचआरडी) और आसियान क्षेत्रीय खनन कार्रवाई केन्द्र (एआरएमएसी) की स्थापना करने के लिए आसियान नेताओं का वक्तव्य.

सम्मेलन में आसियान और इसके मौजूदा एफटीए भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैण्ड के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर वार्ता की शुरुआत हुई.

कारोबार अवसर और प्राप्त संविदाएं

दिसम्बर 2012 को नई परियोजनाएं

देश/ निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
जेस्को लिमिटेड दूसरी मंज़िल, न्यू बिल्डिंग, कमरा 3/10 स्टैंड नंबर 6949 ग्रेस्ट ईस्ट रोड पी.ओ. बॉक्स 33304 10101, लुसाका, जाम्बिया **संपर्क:** श्री हबाड़ु चिमुन्या वरिष्ठ प्रबंधक–अधिप्राप्ति फैक्स : + 260 211 223971 ई–मेल : hnchimunya@zesco.co.zm	**बिजली सेवा विस्तार परियोजना** परियोजना में फिगट्री और चिबोम्बो उप–स्टेशनों के बीच नई 132 केवी ओवरहैड लाइन के निर्माण की जरूरत है.	**विश्व बैंक** 130 मिलियन यूएस डॉलर
हनोई पावर कॉर्पोरेशन निविदा विभाग नं.69, डिन टिन होअंग, होअन कीम डिस्ट्रिक्ट हनोई सिटी, वियतनाम **संपर्क:** टेली : + 844 22200852 फैक्स : + 844 22200853 ई–मेल : dauthau.evnhanoi@gmail.com	**वितरण कार्यकुशलता परियोजना** परियोजना में उप–स्टेशन उपकरणों की आपूर्ति और 110 केवी गिया लाम 2 उप–स्टेशन के लिए सामग्री और ओवरहैड लाइन शामिल है.	**विश्व बैंक** 499 मिलियन यूएस डॉलर
पब्लिक एंटरप्राइज फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मेसीडोनियन रेलवेज – स्कोपज (पीईआरआई) पीई एमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जेलेजनिका 50 बी स्कोपज मेसीडोनिया गणराज्य **संपर्क:** श्री व्लादिमीर त्राजकोवस्की टेली : + 389 75 28 28 51 फैक्स : + 389 2 3230 3651 ई–मेल : vtrajkovski@mz.com.mk	**कॉरिडोर क्रास रेलवे परियोजना** परियोजना में नोगावसी–नेगोटिनो खंड में कुल लगभग 30 किमी लंबाई वाली कॉरिडोर क्रास रेलवे परियोजना के प्रमुख खंडों के साथ ट्रेक नवीकरण शामिल है.	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** € 17.3 मिलियन
एयरपोर्ट 'एलेक्जेण्डर दि ग्रेट'– स्कोपज पी.ओ. बॉक्स 9, 1043 पेट्रोवेक मेसीडोनिया गणराज्य **संपर्क:** श्री निकोलेट तागरिन्स्की टेली : + 389 2 3148 100 ई–मेल : nikolet.tagarinski@mnavigation.mk	**एयर नेविगेशन सर्विस (एएनएस) प्रणाली का उन्नयन** • नई एयर ट्रैफिक प्रबंध (एटीएम) प्रणाली की खरीद, स्थापना और संस्थापन • कई दूरसंचार सुविधाओं का उन्नयन करना और • परामर्शी सेवाएं	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** € 13.35 मिलियन
जार्जिया यूनाइटेड वाटर सप्लाई कंपनी 5, अन्ना पोलितकोवस्कायिया स्ट्रीट 0186 बिलिसी जार्जिया **संपर्क:** टेली : + 995 32 291 90 60 फैक्स : + 995 32 291 60 61 ई–मेल : n.gergedava@water.gov.ge	**शहरी सेवा सुधार निवेश कार्यक्रम–परियोजना 1** कार्यक्षेत्र में पोटि में जल आपूर्ति प्रणालियों और जल उपचार संयंत्र के लिए जलाशयों का निर्माण, पम्पिंग स्टेशन, संप्रेषण लाइनें और वितरण लाइनें शामिल हैं.	**एशियाई विकास बैंक** 55 मिलियन यूएस डॉलर

देश/ निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
काठमांडु घाटी एवं बिरगंज-सिमरा कॉरिडोर वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और नुकसान कटौती परियोजना आयोजना एवं तकनीकी सेवा विभाग वितरण एवं उपभोक्ता सेवाएं ईस्ट दरबारमार्ग काठमांडु, नेपाल **संपर्कः** परियोजना प्रबंधक टेली : +977-1-4153153 फैक्स : +977-1-4153155 ई-मेल : neatscd@gmail.com	**ऊर्जा विस्तार और कार्यकुशलता में सुधार परियोजना** नेपाल के ऊर्जा विस्तार और कार्यकुशलता में सुधार परियोजना में विभिन्न लाइन सामग्री की आपूर्ति एवं सुपुर्दगी तथा लाइनों की स्थापना शामिल है.	**एशियाई विकास बैंक** 41.2 मिलियन यूएस डॉलर
सियरा लिओन रोड अथारिटी ब्लैकहाल रोड, किसी फ्रीटाउन पी. एम. बी 1324 सियरा, लिओन **संपर्कः** महानिदेशक टेली : +232 22 226565 फैक्स : +232 22 222346 ई-मेल : slra_mis@sierratel.sl	**लुंगी-पोर्ट लोको रोड उन्नयन परियोजना** इस परियोजना में शामिल सेवाओं में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल हैः (i) परियोजना के प्रभाव संकेतकों के लिए मूल्यों का निर्धारण जैसे अन्य बातों के साथ-साथ ट्रैफिक की मात्रा, समय की बचत, वाहन परिचालन लागत (ii) अभीष्ट हिताधिकारियों पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सिविल कार्य की समाप्ति पर प्रभाव निर्धारण करना.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 12 मिलियन यूएस डॉलर
केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कं लि. कैपिटल हिल स्क्वायर, दूसरी मंज़िल च्युलु रोड, अपर हिल नैरोबी केन्या गणराज्य **संपर्कः** डॉ. जॉन एम मातिवो प्रमुख तकनीकी सेवाएं टेली : +254 20 4956000 फैक्स : +254 20 4956010 ई-मेल : jmativo@ketraco.co.ke	**नाइल इक्वाटोरियल लेक्स कंट्रीज (केन्या के हिस्से में) के बिजली ग्रिड की अन्तर-संबद्धता** परियोजना में लेसोस उप-स्टेशन से युगांडा बार्डर तक दोहरी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शामिल है.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 245 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय कंपनियों/परामर्शदाताओं को प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड, मुंबई	**विश्व बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त – केन्या बिजली विस्तार परियोजना लॉट-3 के लिए पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की संविदा
मान इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई	**विश्व बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त मिस्त्र की गिजा उत्तरी बिजली परियोजना के लिए 32 इंच की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आपूर्ति की संविदा
अंगेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली	**विश्व बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त नेपाल-भारत बिजली प्रेषण और व्यापार परियोजना के लिए हेतोडा-धालकेबार-इंनारुवा 400 केवी प्रेषण लाइन की डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना की संविदा
कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर	**विश्व बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त आरमेनिया बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए नोरादुज-लिक-वारदेनिस-वायक-वोरोटन 220 केवी ओवरहैड प्रेषण लाइन की डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना करने की संविदा
चढा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली	**अफ्रीकी विकास बैंक** से सहायता प्राप्त लेसोथो की बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए मांनसोनयान 2 मेगावाट लघु हाइड्रो पावर स्टेशन के नवीकरण की संविदा

भारत–चीन व्यापार 76 बिलियन यूएस डॉलर के साथ सर्वोच्च स्तर पर

एशिया की दो महाशक्तियां भारत और चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरी हैं. जहां दोनों देशों का विदेशी व्यापार गत कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है वहीं भारत और चीन के बीच भी परस्पर द्विपक्षीय व्यापार में तेजी की प्रवृत्ति दिखाई दी है. भारत से चीन को निर्यात 2001–02 में लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर था, जो धीरे–धीरे बढ़कर 2005–06 में 6.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इसके बाद निर्यातों में 18 प्रतिशत की दर (सीएजीआर) से बढ़ोतरी हुई और ये 2011–12 में 18 बिलियन यूएस डॉलर हो गये.

चीन से भारत के आयात में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है. चीन से भारत का आयात 2005–06 के 11 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2011–12 में लगभग 58 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इस अवधि में सीएजीआर 32 प्रतिशत रही. आयात में वृद्धि मुख्यतः लौह एवं इस्पात, परिवहन उपकरण, निर्मित उर्वरक, परियोजना माल, स्वर्ण और धातुनिर्माण के आयात में वृद्धि के कारण हुई. इसके कारण चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 2011–12 के दौरान 75.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो 2010–11 के 58.9 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक था **(चार्ट)**.

वर्ष 2012–13 (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल और वैश्विक मंदी के कारण भारत से निर्यात 8.4 बिलियन यूएस डॉलर रहे, जबकि 2011–12 में इसी अवधि के दौरान 11.2 बिलियन यूएस डॉलर था. 2012–13 की इसी अवधि में आयात गत वर्ष के 39 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 37 बिलियन यूएस डॉलर रहे हैं.

भारत से बढ़ते निर्यात के कारण चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान बन गया है जिसका भारत के कुल निर्यातों में लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा है. आयात के मामले में 2011–12 के दौरान चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बनकर उभरा है जिसने जापान, यूके, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैण्ड और यूएसए को पीछे छोड़ दिया है जो 2001–02 के दौरान भारत के प्रमुख आयात स्रोत थे. इसके परिणामस्वरूप भारत के कुल आयात में चीन का हिस्सा 2001–02 के 4 प्रतिशत हिस्से की तुलना में गत दशक में लगभग 12 प्रतिशत हो गया.

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत से चीन को निर्यात में मुख्यतः अयस्क, मेटल स्क्रैप और भस्म रहे जिनका देश के कुल निर्यात में लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा रहा. इसके बाद कपास, तांबा और वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद और जैविक रसायनों का स्थान रहा. दूसरी ओर, चीन से आयात की प्रमुख मदों में बिजली की मशीनरी और उपकरण, (चीन से भारत के कुल आयात में 24 प्रतिशत हिस्सा,) बॉयलर एवं भारी मशीनरी, परियोजना माल, जैविक रसायन, उर्वरक और लौह एवं इस्पात शामिल हैं.

चार्ट : चीन के साथ भारत का व्यापार (बिलियन यूएस डॉलर)

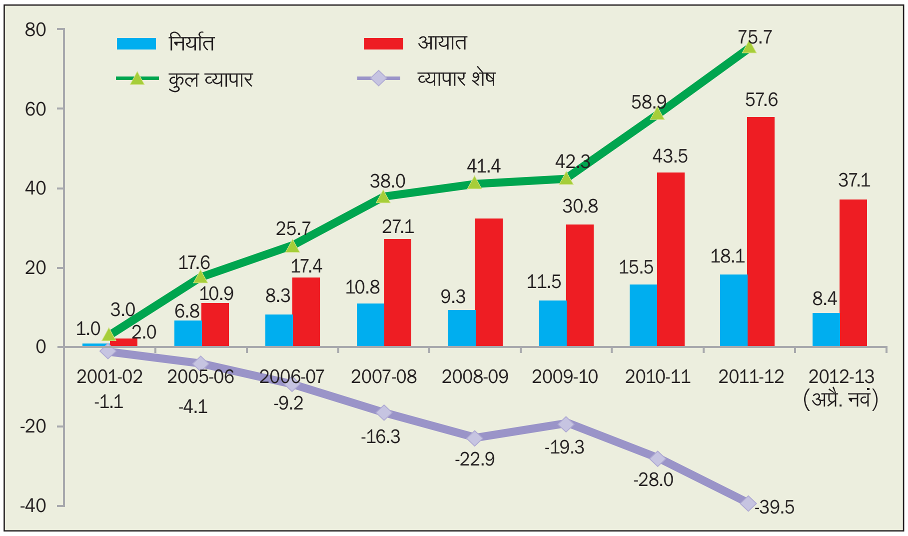

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई), भारत सरकार

भारत–चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद

इस मंच की स्थापना बदलते अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में दोनों देशों को प्रभावित करने वाले बृहत–आर्थिक मुद्दों पर एक साझा मंच के रूप में कार्य करने की परिकल्पना के रूप में दिसम्बर 2010 में हुई भारत–चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद प्रक्रिया में बेहतरीन पद्धतियों को साझा करने, चुनौतीपूर्ण घरेलू आर्थिक मुद्दों पर सहयोग और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना भी शामिल था. पहला भारत–चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद सितम्बर 2011 में बीजिंग में संपन्न हुआ.

इसी अनुक्रम में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दूसरा भारत–चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद नवम्बर 2012 में नई दिल्ली में भारत के योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच संपन्न हुआ. संवाद के दौरान भारत और चीन ने व्यापार बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच विकास और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने, निवेश में वृद्धि और वाणिज्यिक परिचालनों को बढ़ाने के लिए किसी भी देश में वित्तीय संस्थाओं के बाजार अभिगम को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की आर्थिक रणनीति तैयार की.

दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने, बृहत–आर्थिक नीतियों के संप्रेषण को सुदृढ़ बनाने और व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए भी कई मुद्दों पर सफलतापूर्वक बातचीत की तथा 2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ाने की परिकल्पना की. इसके लिए दोनों देश बाजार अवरोधों को हटाने, व्यापार विनिमय बढ़ाने और परिवहन लिंक में सुधार सहित कर मुक्त व्यापार पर अधिक बल देने के लिए सहमत हुए.

एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ प्रभावी बाज़ार प्रवेश रणनीति के रूप में ऋण–व्यवस्थाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया है. एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सॉवरिन सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित ऋण शर्तों पर विकासपरक और बुनियादी परियोजनाएं, उपकरण, माल एवं सेवाएं आयात करने के लिए ऋण–व्यवस्थाओं की सुविधा प्रदान करता है. भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेजों के परक्रामण के बदले एक्ज़िम बैंक से पात्र राशि का दायित्व रहित भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है. सरकार के आदेश पर प्रदान की जाने वाली ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को माल के पोतलदान पर अपफ्रंट संविदा मूल्य की 100 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करता है बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य की कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवाएं भारत से सोर्स की जानी चाहिए. एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को जोखिम रहित, दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं.

यथा 31 दिसम्बर, 2012 को अफ्रीका, एशिया, लातिनी अमेरिका, यूरोप, ओशियाना और सीआईएस के 74 देशों को शामिल करते हुए एक्ज़िम बैंक की 167 ऋण–व्यवस्थाएं परिचालनरत थीं जिनके अंतर्गत 8.67 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण–राशि भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं. ये ऋण–व्यवस्थाएं विविध परियोजनाओं के निर्यात की उत्प्रेरक हैं. भारतीय परियोजनाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए प्रदान की जा रही ऋण–व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देश में विकास के साथ–साथ भारतीय विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश एवं सहयोग से अक्तूबर–दिसम्बर 2012 तिमाही के दौरान निम्नलिखित ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की हैं :

- तंजानिया सरकार को तंजानिया में दार एस सलाम और चालिन्जी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं को बढ़ाने के लिए 178.125 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक द्वारा इससे पहले भी तंजानिया सरकार को ट्रैक्टरों, पंपों और उपकरणों, वाहनों आदि की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए कुल 111.56 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है.
- स्वाजीलैण्ड सरकार को स्वाजीलैण्ड में कृषि के विकास एवं यंत्रीकरण के लिए 37.9 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की. एक्ज़िम बैंक ने इससे पहले स्वाजीलैण्ड में आईटी पार्क की स्थापना के वित्तपोषण हेतु 20 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की है.
- क्यूबा सरकार को क्यूबा में कामागुये प्रोविन्स में दूध पाउडर प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना के वित्तपोषण हेतु 5 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक द्वारा क्यूबा को प्रदान की गई यह पहली ऋण–व्यवस्था है.
- गुयाना सरकार को मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए 19 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने गुयाना सरकार को इससे पहले जार्जटाउन में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, यातायात संकेत प्रणाली परियोजना और सिंचाई परियोजना के लिए 44.1 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.
- मालावी सरकार को ग्रीनबेल्ट इनीशिएटिव के अंतर्गत सिंचाई नेटवर्क के विकास, सलिमा में परिष्कृत चीनी प्रसंस्करण उपकरणों की स्थापना और ईंधन भण्डारण सुविधाओं के विकास के लिए 76.5 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कीं. एक्ज़िम बैंक ने इससे पहले कपास की ओटाई सुविधाएं, ग्रीनबेल्ट्स पहल के लिए उपकरणों की आपूर्ति, दाल प्रसंस्करण संयंत्र आदि की स्थापना के लिए 156.5 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की है.
- घाना सरकार को घाना में शुगर प्लांट परियोजना के वित्तपोषण के लिए 35 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने इससे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि और परिवहन योजनाओं, रेलवे वैगन की अधिप्राप्ति, मत्स्य पालन और मत्स्य प्रसंस्करण परियोजना आदि के वित्तपोषण के लिए 148.72 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की है.
- सेशेल्स सरकार को सेशेल्स विकास बैंक द्वारा निधिक सहायता प्राप्त 7 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भारत से माल एवं सेवाओं के आयात के वित्तपोषण के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं. एक्ज़िम बैंक ने सेशेल्स सरकार को इससे पहले वाहनों, दवाइयों, खाद्य मदों आदि की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए 23 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की है.
- सेनेगल सरकार को सेनेगल में मछली पालन विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए 19 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने इससे पहले कृषि मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, बसों की आपूर्ति और कल–पुरजे, सिंचाई परियोजना आदि के वित्तपोषण के लिए 145.45 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की है.
- गाम्बिया गणराज्य सरकार को गाम्बिया में राष्ट्रीय विधानसभा भवन को पूर्ण करने के उद्देश्य से भारत से परामर्श सेवाओं सहित पात्र माल, सेवा, मशीनरी और उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 16.88 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्रीमती गीता पूजारी,
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
सेन्टर एक बिल्डिंग, 21 मंज़िल,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ़ परेड,
मुंबई – 400 005

फोन : (022) 22162073
(022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई–मेल : eximloc@eximbankindia.in

निर्यात बढ़ाने के लिए एमओसीआई द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा

केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री श्री आनंद शर्मा ने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर 2012 में अतिरिक्त प्रोत्साहनों की घोषणा की. श्री शर्मा ने कहा कि रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज के लिए 2 प्रतिशत सरकारी अनुदान योजना को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है जो हस्तशिल्प, गलीचों, हथकरघा, तैयार वस्त्रों, संसाधित कृषि उत्पादों, खेलकूद के सामान और खिलौनों सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर उपलब्ध है. यह योजना 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली थी. इसके साथ ही सभी क्षेत्रों के लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. ब्याज के लिए 2 प्रतिशत सरकारी अनुदान योजना को इंजीनियरिंग क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है. श्री शर्मा ने सार्क क्षेत्र के देशों, अफ्रीका और म्यांमार के लिए एक्ज़िम बैंक के जरिये परियोजना निर्यात हेतु ब्याज के लिए 2 प्रतिशत सरकारी अनुदान की 'प्रायोगिक योजना' की शुरुआत करने की भी घोषणा की. परियोजना के बारे में श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना प्रारंभ में 500 मिलियन यूएस डॉलर से तत्काल परिचालित की जाएगी. ब्याज के लिए सरकारी अनुदान को क्रेता ऋण योजना से जोड़ा जायेगा. क्रेता ऋण योजना को गत वित्तीय वर्ष में शुरु किया गया था जो एक्ज़िम बैंक, ईसीजीसी और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के जरिये लागू की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि योजना का उद्देश्य एक्ज़िम बैंक के माध्यम से पेय जल, आवास, सिंचाई, रोड परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे बुनियादी संरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक रियायती ऋण प्रदान कर इन देशों को भारत का निर्यात बढ़ाना है.

नवम्बर में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर खुदरा ऋण में वृद्धि लेकिन उद्योग को ऋण की गति धीमीः भारतीय रिज़र्व बैंक

नवम्बर में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर खुदरा ऋण में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की सबसे उच्च दर है. कई बैंकों ने खुदरा ऋण बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी अथवा घटा दी. खुदरा ऋणों में वाहन ऋणों में अक्तूबर के 22.2 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई. आवास ऋणों में अक्तूबर के 12.1 प्रतिशत की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. औद्योगिक ऋणों में गत माह की 15.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में नवम्बर में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. जबकि नवम्बर 2011 में इसमें 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. उद्योगों को कुल ऋणों में गिरावट खनन और उत्खनन, खाद्य प्रसंस्करण, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और न्यूक्लीयर ईंधन, रसायन और रसायन उत्पाद, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रमुख उप–क्षेत्रों में दर्ज की गई है.

लोक सभा द्वारा कंपनी विधेयक 2011 पारित

लोक सभा ने कंपनी विधेयक 2011 को अनुमोदित कर नये सामयिक विधेयक के लिए रास्ता प्रशस्त किया. नया विधेयक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर बदलते आर्थिक और वाणिज्यिक माहौल के अनुरूप है. दिसम्बर 2012 में लोकसभा पारित विधेयक देश में कंपनियों पर विनियमन के मौजूदा विधान अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करेगा. संशोधित विधेयक कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों से निपटने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) को अधिक सांविधिक अधिकार प्रदान करेगा, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा तथा चिट फण्डों की खामियों को नियंत्रित करेगा. विधेयक का उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अधिक पारदर्शी बनाना, स्वतंत्र निदेशकों को अधिक जिम्मेदार बनाना और कॉर्पोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य करना भी है. विधेयक के पारित होने से एसएफआईओ के साथ राज्य एवं केन्द्रीय जाँच एजेंसियों, आयकर विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच अधिक बेहतर तालमेल होगा. नये विनियमनों के अनुसार एसएफआईओ को किसी भी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में केस दायर करने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय जैसी अन्य जाँच एजेंसियों के साथ समन्वय के अधिकार मिलेंगे.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में 8,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराई.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 दिसम्बर, 2012 को खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर वित्तीय प्रणाली में 8,000 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की. मौद्रिक नीति और वर्तमान एवं संभाव्य नकदी स्थितियों के मौजूदा आकलन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहु–प्रतिभूति (मल्टी सिक्युरीटी) नीलामी के जरिए 4 जनवरी, 2013 को कुल 8,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर खुले बाज़ार में परिचालन करने का निर्णय लिया.

भारत का विदेश व्यापारः अप्रैल–दिसम्बर 2012

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल–दिसम्बर 2012 (2012–13 के लिए) अवधि में निर्यातों का संचयी मूल्य गत वर्ष की इसी अवधि के 226.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 211.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा. इसमें 6.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई. जबकि संचयी आयात गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 363.7 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर 2012 के दौरान 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 365 बिलियन यूएस डॉलर रहा. व्यापार घाटा भी अप्रैल–दिसम्बर 2012 के दौरान 153.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो अप्रैल–दिसम्बर 2011 के दौरान 137.5 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे से अधिक था.

आईओआर–एआरसी में भारत की व्यापार और निवेश संभावना : एक्ज़िम बैंक का अध्ययन

एक्ज़िम बैंक ने सितम्बर 2012 में 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम असोसिएशन : भारत की व्यापार और निवेश संभावना के बारे में अध्ययन' विषय पर अपना प्रकाशन जारी किया. अध्ययन में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभावित करने वाली कठिनाइयों के बावजूद आईओआर–एआरसी क्षेत्र में हाल में अच्छा कार्य होने का अनुमान है. वर्ष 2011 में इंडियन ओशन रिम असोसिएशन के सदस्य देशों का संयुक्त जीडीपी 2010 में 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की तुलना में बढ़कर 6.5 ट्रिलियन और 2016 तक 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन का कुल व्यापार 2005 के 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2010 में 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया, जिसमें इस अवधि में 14.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई. यह निर्यात और आयात दोनों में अनुकूल वृद्धि निष्पादन को प्रदर्शित करती है. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन सदस्य देशों का कुल अंत: क्षेत्रीय व्यापार 2005 के 506.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2010 में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया. अध्ययन में इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध हाल के वर्षों में सुदृढ़ हुए हैं और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए अवसर मौजूद हैं. अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन के अन्य सदस्य देशों के साथ 2001–2010 के दशक के दौरान भारत का कुल व्यापार 19 बिलियन यूएस डॉलर से आठ गुना से अधिक बढ़कर 156.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इस क्षेत्र को 2010 में भारत का निर्यात 69 बिलियन यूएस डॉलर और आयात 87.3 बिलियन यूएस डॉलर रहे. अध्ययन में इस बात पर भी बल दिया गया है कि अप्रैल 1996 से मार्च 2010 के दौरान इस क्षेत्र में भारत का संचयी प्रत्यक्ष निवेश 82.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो इस अवधि में भारत के वैश्विक विदेशी निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक है. इस क्षेत्र के देशों को भारत से निर्यात की संभाव्य मदों, (जिनकी अध्ययन में पहचान की गई है) में मशीनरी, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवहन वाहन, चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक और वस्तुएं तथा लौह एवं इस्पात शामिल हैं.

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस संस्मारक व्याख्यान माला : लार्स थनेल का व्याख्यान

एक्ज़िम बैंक ने 10 दिसम्बर, 2012 को मुंबई में अपने तीसरे संस्मारक व्याख्यान का आयोजन किया. यह व्याख्यान विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के पूर्व सीईओ डॉ. लार्स थनेल ने दिया. डॉ. लार्स थनेल ने 'विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका और भारत एवं भारतीय कंपनियों के लिए अवसर' विषय पर चर्चा की.

एक्ज़िम बैंक ने अपने परिचालनों के 30 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में 2012 में व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की. श्रृंखला में पहला व्याख्यान जून 2012 में डॉ. कौशिक बसु, तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने; दूसरा व्याख्यान नवम्बर 2012 में नई दिल्ली में कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक आर्थिक प्रणालियों की प्रोफेसर और सेंटर फॉर टांजिशन इकोनोमीज की निदेशक प्रो. पदमा देसाई ने दिया.

अपना व्याख्यान देते हुए डॉ. थनेल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में वर्तमान में अनेक अनिश्चितताएं हैं. यूरोप मंदी की चपेट में है और उसे अपने ऋण भार से निपटना है जिसके कारण विकास धीमा है और बेरोजगारी अधिक है. अमेरिका आवास स्थिति में सुधार होने और कम ऊर्जा मूल्यों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धी स्थिति के आधार पर धीर–धीरे मंदी से उभर रहा है. वास्तविक विकास उभरते बाज़ारों में होना है. इन देशों में नया मध्यम वर्ग, हाल में मिले प्राकृतिक संसाधन और जनसांख्यिकी लाभ विकास के संवाहक बने रहेंगे. अफ्रीका में काफी नये अवसर मिलेंगे. हालांकि दुनिया में असंतुलन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः मंदी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

डॉ. थनेल ने अपने व्याख्यान में कहा कि नई स्थिति असंतुलित विकास के साथ मल्टीपोलर दुनिया पर आधारित होगी. जोखिम टालने और बैंकों में पूंजी की कमी के कारण वित्तपोषण के संसाधन कम होंगे, किन्तु सरकारी–निजी सहभागिता को प्रमुखता मिलेगी. बड़ी और छोटी निजी कंपनियों को इन अवसरों का लाभ उठा कर आगे बढ़ने और अपने व्यवसाय का विकास करना चाहिए तथा उन्हें नये बाज़ारों की तलाश भी करनी चाहिए.

एक्ज़िम बैंक के स्थापना दिवस पर प्रो. भगवती का व्याख्यान

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और विधि के प्रोफेसर तथा मुक्त व्यापार के सर्वाधिक समर्थकों में से एक प्रो. जगदीश भगवती ने 21 नवम्बर, 2012 को मुंबई में एक्ज़िम बैंक वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान दिया. उन्होंने 'विश्व व्यापार प्रणाली का विकास : भारत के लिए विकल्प' विषय पर अपना व्याख्यान दिया. व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने की.

एक्ज़िम बैंक का वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान मार्च 1982 में बैंक द्वारा अपना कारोबार आरंभ करने के उपलक्ष में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है. बैंक की वार्षिक व्याख्यान माला की शुरुआत 1986 में हुई थी और इसने वर्तमान में मुंबई के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम के रूप में अपनी जगह बना ली है. व्याख्यान में बड़ी संख्या में श्रोतागण आते हैं जिनमें व्यवसायी, प्रोफेशनल, बैंकर और शिक्षाविद शामिल हैं. वार्षिक व्याख्यान का उद्देश्य अर्थव्यवस्था व वैश्विकरण के संबंध में वैश्विक स्तर पर जारी चर्चा के बारे जानकारी देने, संवर्धन करने तथा उसमें योगदान देना है. बैंक के स्थापना दिवस व्याख्यान के पूर्व वक्ताओं में श्री सुपाचई पैनिचपाकड़ी, महासचिव, अंकटाड; विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष प्रो. निकोलस स्टर्न; लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स के प्रोफेसर लार्ड मेघनाद देसाई; न्यूजीलैण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जेम्स बोलगर; संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के पूर्व प्रशासक डॉ. केमल दर्विश तथा चाइना सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष प्रो. यु यांगडिंग शामिल हैं जिन्होंने 2011 में 'विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्संतुलन' पर अपना व्याख्यान दिया था.

10 भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी के निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीतियां

टेक्सटाइल भारत की प्रमुख निर्यात मदों में एक है जिसका भारत की निर्यात आय में 11 प्रतिशत से अधिक योगदान है. भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र ने वस्त्र इकाइयों की पूंजीगत मांग को पूरा करने के लिए इस उद्योग की एक शाखा के रूप में शुरुआत की. शुरुआती वर्षों में इसके विकास में बाधाएं आईं किन्तु टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र ने कोटा समाप्ति के बाद टेक्सटाइल उद्योग की क्षमता विस्तार में वृद्धि से नवोन्मेषी स्वचालित मशीनरी का निर्माण करना आरंभ किया. भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) का भी इसके विकास में योगदान रहा.

वर्ष 2010 में टेक्सटाइल मशीनरी का वैश्विक व्यापार 32 बिलियन यूएस डॉलर आंका गया था. टेक्सटाइल मशीनरी का सबसे बड़ा निर्यातक जर्मनी (16 प्रतिशत हिस्सा) है, इसके बाद चीन (14 प्रतिशत) और इटली (11 प्रतिशत) का स्थान है. भारत का 23वां स्थान है जिसका वैश्विक निर्यात में 0.5 प्रतिशत हिस्सा है. आयात के मामले में भारत वैश्विक आयात में 4 प्रतिशत हिस्से के साथ चौथा सबसे बड़ा आयातक है **(तालिका)**.

विकास के लिए रणनीतियां

क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन में हुई प्रगति टेक्सटाइल मशीनरी के निर्यात को बढ़ाने में सहायक होगी.

निर्यात विशाखन: भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी के प्रमुख बाजार चीन, स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी और इंडोनेशिया हैं जिनका कुल निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है. चीन और जर्मनी दो प्रमुख वैश्विक आयातक हैं जिनको हम आपूर्ति कर भी रहे हैं. अन्य प्रमुख आयातकों में जापान, फ्रांस, यूके, टर्की, इटली और कनाड़ा शामिल हैं जिनको हमारे निर्यात कम रहे हैं. ये देश 10 बिलियन यूएस डॉलर का बाज़ार उपलब्ध कराते हैं, जो वैश्विक आयात का लगभग एक–तिहाई है. इन देशों से टेक्सटाइल मशीनरी के आयात में भी हमारा हिस्सा बहुत कम है. चीन के आयात में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत, जर्मनी में 1 प्रतिशत, इटली में 0.9 प्रतिशत, जापान में 0.2 प्रतिशत, टर्की में 0.8 प्रतिशत, कनाडा और फ्रांस (नगण्य शेयर) रहा है. इससे यह स्पष्ट है कि हमें अपने बाज़ारों का विशाखन करने की जरूरत है. और यह विशाखन प्रौद्योगिकीय सक्षमता, नवोन्मेष और आर एण्ड डी के जरिये हो सकता है.

आर एण्ड डी पर बल: भारत में इस क्षेत्र में हाई–टेक उत्पादों की कमी का महत्वपूर्ण कारण आर एण्ड डी पर कम व्यय होना है. विकसित देशों में इस क्षेत्र पर वैश्विक खर्च बहुत अधिक (बिक्री का लगभग 5 प्रतिशत) है. चीन जैसे प्रमुख विकासशील देश भी इस क्षेत्र में आर एण्ड डी पर बिक्री का लगभग 2 प्रतिशत खर्च करते हैं. इसकी तुलना में भारत में इस क्षेत्र में आर एण्ड डी पर बिक्री का लगभग 0.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है. भारत को इस क्षेत्र में अपने आर एण्ड डी व्यय को बढ़ाने की जरूरत है. इस मामले में बड़े उद्यमों और लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए अलग–अलग रणनीतियां होनी चाहिए.

मझौले उद्यमों के लिए निवेश सीमा बढ़ाना: टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र में अनेक एसएमई (80 प्रतिशत से अधिक) इकाइयां हैं जो संपूर्ण मशीनरी, सभी प्रकार के घटक/पुर्जे, सहायक उपकरण, परीक्षण और मॉनिटरिंग उपकरण एवं अनुषंगी औजारों का निर्माण कर रही हैं. इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपेक्षित स्तर के निवेश और सरकारी सहयोग की जरूरत है. भारत में किसी इकाई को एमएसएमई में वर्गीकृत करने के लिए प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा काफी कम है जो मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हतोत्साहित करती है. भारत में मझौले उद्यमों में निवेश सीमा लगभग 1–2 मिलियन यूएस डॉलर (अर्थात 5–10 करोड़ रुपये) तय की गई है. जबकि भारत जैसे विकासशील देशों (अर्थात चीन, फिलीपीन्स और थाइलैण्ड) में भी एसएमई के रूप में किसी विनिर्माण इकाई को वर्गीकृत करने के लिए पूंजी निवेश की सीमा काफी अधिक है.

समूह–आधारित दृष्टिकोण: एमएसएमई इकाइयां प्रायः कमजोर आर्थिक आधार वाली होती हैं किंतु यदि वे समूहों में कार्य करें तो साझा कार्यकलाप, सामूहिक विपणन और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित कर प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तरों तक पहुंच सकती हैं. टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र में भी एमएसएमई इकाइयां समूह–आधारित दृष्टिकोण (क्लस्टर) अपनाकर ही मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ सकती हैं. चीन और कोरिया जैसे देशों ने समूह–आधारित दृष्टिकोण अपनाकर ऐसे समूह विकसित किये हैं जहां आपूर्तिकर्ता और वेंडरों के बीच ताल–मेल से नवोन्मेषी, सस्ते और बेहतर उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं. सूरत, सुरेन्द्रनगर और अहमदाबाद में एमएसएमई इकाइयों को ऐसे दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र की सफलता मुख्यतः प्रौद्योगिकी और ब्रांडिंग पर निर्भर है. कई भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी निर्माताओं ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप शुरू किये हैं, जिससे यह क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है.

तालिका: वस्त्र मशीनरी के दुनिया के शीर्ष निर्यातक और आयातक 2010

निर्यातक				आयातक			
रैंक	देश	मिलियन यूएस डॉलर	प्रतिशत हिस्सा	रैंक	देश	मिलियन यूएस डॉलर	प्रतिशत हिस्सा
विश्व		32,482	100.0	विश्व		31,054	100.0
1	जर्मनी	5,240	16.1	1	चीन	4,380	14.1
2	चीन	4,513	13.9	2	संयुक्त राज्य अमेरिका	3,527	11.4
3	इटली	3,489	10.7	3	जर्मनी	1,787	5.8
4	कोरिया गणराज्य	2,864	8.8	**4**	**भारत**	**1,282**	**4.1**
5	जापान	2,576	7.9	5	जापान	1,257	4.0
6	पोलैण्ड	1,644	5.1	6	टर्की	1,165	3.8
7	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,431	4.4	7	फ्रांस	1,034	3.3
8	स्विट्जरलैण्ड	1,253	3.9	8	यूनाइटेड किंगडम	993	3.2
9	थाइलैण्ड	1,075	3.3	9	इटली	980	3.2
10	टर्की	966	3.0	10	कनाडा	751	2.4
23	**भारत**	**174**	**0.5**				
मेमो मदें							
विश्व का 5 वर्षीय सीएजीआर (निर्यात)			−0.2%	विश्व का 5 वर्षीय सीएजीआर (आयात)			−0.1%
भारत का 5 वर्षीय सीएजीआर (निर्यात)			13.5%	भारत का 5 वर्षीय सीएजीआर (आयात)			−11.2%

स्रोत: पीसीटीएएस

वर्ष 2012–13 में भारत के कृषि निर्यात में विस्तार होने की उम्मीद है. भारत का कृषि निर्यात 2012–13 की पहली तीन तिमाहियों में 23.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 22.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का था. यह वृद्धि मुख्यतः गुवार गम के निर्यात में अप्रैल–दिसम्बर 2011 के 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर 2012 में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी के कारण हुई है **(तालिका)**.

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती मांग के चलते गत वर्ष की तुलना में गुवार गम के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है. गुवार गम गुवार के बीज का तत्व है जिसे तेल और प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग में सील लगाने में प्रयुक्त किया जाता है. कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण गत डेढ वर्ष में गुवार गम की वैश्विक मांग बढ़ी है. तदनुसार भारत के कुल निर्यात में गुवार गम का हिस्सा भी अप्रैल–दिसम्बर 2011 के दौरान 0.7 प्रतिशत से तीन गुना बढ़ कर अप्रैल–दिसम्बर 2012 में 2.1 प्रतिशत हो गया.

भारत से कृषि निर्यातों को बढ़ाने वाला अन्य प्रमुख पण्य चावल रहा है. वर्ष 2012–13 की पहली तीन तिमाहियों में भारत से चावल का निर्यात (बासमती और गैर–बासमती चावल) गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 4.4 बिलियन अमरीकी डॉलर को गया, जिससे भारत के कुल निर्यात में चावल निर्यात का हिस्सा अप्रैल–दिसम्बर 2011 के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल–दिसम्बर 2012 में 2.1 प्रतिशत हो गया. चावल के निर्यात में वृद्धि मोटे तौर पर 2012–13 की पहली छमाही के दौरान भारत के गैर–बासमती चावलों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का योगदान रहा जो गत वर्ष की तुलना में आठ गुना से अधिक बढ़कर 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गये. यह मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2011 में बासमती चावलों के निर्यात पर तीन वर्ष के प्रतिबंधों के बाद गैर–बासमती चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के निर्णय के कारण हुआ है. बासमती चावल का निर्यात 2012–13 की पहली छमाही के दौरान 4.7 प्रतिशत बढ़कर 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया. यह वृद्धि मुख्यतः खाड़ी देशों, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुगन्धित लंबे चावलों की मांग के कारण हुई है. भारत से बासमती चावलों के निर्यात का आधे से अधिक हिस्सा ईरान और सऊदी अरब को जाता है.

तालिकाः भारत से कृषि निर्यात

पण्य	अप्रै–दिस. 2011 मिलियन यूएस डॉलर	अप्रै–दिस. 2012 मिलियन यूएस डॉलर	वृद्धि (प्रतिशत)	भारत के कुल निर्यात में हिस्सा (प्रतिशत)
अनाज	4097.3	6563.3	60.19	3.10
क) चावल	3185.4	4370.8	37.21	2.07
ख) गेहूं	133.5	1280.1	858.90	0.60
ग) अन्य	778.4	912.5	17.22	0.43
दालें	187.4	149.6	–20.21	0.07
तम्बाकू	576.7	667.5	15.75	0.32
क) अनिर्मित	406.1	504.5	24.24	0.24
ख) निर्मित	170.6	163.0	–4.47	0.08
मसाले 2053.8	2170.6	5.69	1.03	
गिरीदार फल और बीज	1925.2	1534.1	–20.32	0.73
क) सीएसएनएल सहित काजू	712.4	560.1	–21.39	0.26
ख) तिल और नाइगर बीज	438.5	390.7	–10.91	0.18
ग) मूंगफली	774.2	583.3	–24.66	0.28
ऑयल मील	1719.6	1805.3	4.99	0.85
गुवार गम मील	1654.7	4464.6	169.82	2.11
कस्तूर तेल	759.7	568.0	–25.24	0.27
चमड़ा	38.3	49.5	29.31	0.02
चीनी और सीरा	1317.0	1472.8	11.84	0.70
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	1826.4	1892.8	3.63	0.89
क) ताजा फल और सब्जियां	810.2	772.6	–4.64	0.37
ख) फल/सब्जियों के बीज	39.9	47.7	19.45	0.02
ग) प्रसंस्कृत और विविध प्रसंस्कृत मदें	976.3	1072.5	9.85	0.51
मांस और तैयारियां	2082.3	2312.4	11.05	1.09
मुर्गीपालन और डेरी उत्पाद	142.9	241.1	68.72	0.11
पुष्पकृषि उत्पाद	56.3	58.1	3.25	0.03
स्प्रिट और बीवरेज	211.8	256.5	21.10	0.12
चाय	710.7	586.2	–17.51	0.28
कॉफी	665.1	604.4	–9.13	0.29
समुद्री उत्पाद	2748.8	2701.2	–1.73	1.28
कुल कृषि उत्पाद (बागान और समुद्री उत्पादों सहित)	22774.1	28098.1	23.38	13.28

P: प्रावधान

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एक्ज़िम बैंक भारत विश्लेषण

एक और पण्य, जिसने कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वद्धि की है, वह मसालों का निर्यात है. अप्रैल–दिसम्बर 2012 के दौरान भारत के मसालों के निर्यात में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा निर्यात बढ़कर 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के हो गये जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात हुए थे.

अप्रैल–दिसम्बर 2012 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यातों में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले अन्य प्रमुख पण्यों में मांस उत्पाद (11.1 प्रतिशत की वृद्धि), संसाधित खाद्य पदार्थ (3.6 प्रतिशत), ऑयल मील (5 प्रतिशत) और चीनी एवं सीरा (11.8 प्रतिशत) शामिल हैं.

बागान निर्यात (चाय एवं कॉफी सहित) अप्रैल–दिसम्बर 2011 के 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज कर अप्रैल–दिसम्बर 2012 में 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा. 2011–12 में उत्तरी भारत में लंबे समय तक सर्दी पड़ने और तमिल नाडु एवं केरल (दक्षिण भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य) में लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण कम उत्पादन के चलते चाय का निर्यात कम हुआ. अप्रैल–दिसम्बर 2012 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत की कमी हुई और ये 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के हुए.

कुल मिलाकर भारत के समग्र निर्यातों में 2012 की पहली तीन तिमाहियों में भारत के कृषि निर्यात (बागान और समुद्री उत्पादों सहित) का हिस्सा 13.3 प्रतिशत रहा है, जबकि गत वर्ष की इसी अवधि यह 10.1 प्रतिशत था.

संसाधन संपन्न अफ्रीका में भारतीय निवेश

अफ्रीका के बारे में निवेशकों की राय और क्षेत्र की विकास संभावना के बारे में सकारात्मक बदलाव आया है जिसके चलते गत दशक में अफ्रीका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में तेजी से वृद्धि हुई है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका दुनिया में सर्वाधिक निवेश प्रतिलाभ देने वालों में से एक है. अफ्रीका गत कई वर्षों से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य स्थान रहा है.

अफ्रीका में भारत का कारोबार और निवेश मोटे तौर पर छोटे एवं मझौले उद्यमों एवं व्यापारियों द्वारा संचालित होता था. लेकिन भारत से अफ्रीका में हुआ हालिया निवेश भारत की बड़ी कंपनियों से संचालित है. वस्तुओं के मूल्यों में लगातार होती वृद्धि तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में ऊर्जा एवं कच्चे माल की बढ़ती मांग इन कंपनियों के लिए फायदेमंद सिद्ध हुई है.

अप्रैल 1996 से मार्च 2012 के दौरान अफ्रीका में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में अनुमोदित संचयी भारतीय निवेश 33.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जिसका भारत के कुल एफडीआई बहिर्वाह (164.3 बिलियन यूएस डॉलर) में 20.1 प्रतिशत का उल्लेखनीय हिस्सा रहा है. अफ्रीका में भारतीय एफडीआई बहिर्वाह 2007–08 में 2.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2011–12 में 7.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. भारत के एफडीआई बहिर्वाह के प्रमुख गंतव्य मॉरीशस, सूडान, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और लीबिया रहे **(तालिका)**. अफ्रीका में भारत के निवेश का लगभग 90 प्रतिशत कर पनाह वाले देश मॉरीशस में हुआ. भारतीय एफडीआई बहिर्वाह में अफ्रीका का हिस्सा 2007–08 के 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 24.3 प्रतिशत हो गया. अफ्रीका में भारतीय निवेश मुख्यतः भारत की भारती एयरटेल द्वारा 15 अफ्रीकी देशों में जैन टेलीकॉम के मोबाइल परिचालनों को 10.7 बिलियन यूएस डॉलर में अधिग्रहण के कारण 2009–10 में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2010–11 में 13.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया.

अफ्रीका में भारतीय निवेश तेल एवं गैस, बुनियादी संरचना (रोड, बंदरगाह) दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, हॉस्पिटलिटी सहित उद्योगों के विविध खण्डों में हैं. इन निवेशों में से अनेक निष्कर्षण क्षेत्र में किये गये हैं. इनके अलावा, भारत से अफ्रीका में किया गया एफडीआई बाज़ार खोज खंड में हैं. टाटा मोटर्स और महिन्द्रा एंड महिन्द्रा जैसे कई प्रमुख ऑटो उद्योगों ने अफ्रीका में निवेश किया है. मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है अफ्रीका में भारतीय निवेश संसाधन खोज, बाज़ार खोज और कार्यकुशलता खोज क्षेत्रों में किये गये हैं. 2011–12 में अफ्रीका में प्रमुख भारतीय निवेशकों में रिलायंस ऑयल एंड गैस, टाटा पावर, ईटीएचएल कम्युनिकेशन्स, बायो विन कॉरपोरेशन, आरएचसी फाइनेंशियल सर्विसेज़, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुजलान एनर्जी लि., एस्सार सर्विसेज, भारती एयरटेल, ब्लूम फाउंडेशन, गोदरेज आदि शामिल हैं.

वर्ष 2011–12 में अफ्रीका का विनिर्माण क्षेत्र भारत के एफडीआई का प्रमुख प्राप्तकर्ता रहा, जिसका अफ्रीका में भारत के कुल एफडीआई में 53.5 प्रतिशत हिस्सा रहा. अन्य क्षेत्रों में वित्तीय, बीमा, रियल इस्टेट और कारोबारी सेवाएं (27.7 प्रतिशत), निर्माण (8.1 प्रतिशत), सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं (3.6 प्रतिशत), थोक, खुदरा व्यापार, रेस्त्रां एवं होटल (3 प्रतिशत), परिवहन, भण्डारण एवं संचार सेवाएं (2.6 प्रतिशत) और कृषि, खनन और सहायक कार्यकलाप (0.8 प्रतिशत) शामिल हैं.

तालिकाः अफ्रीका में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में अनुमोदित भारतीय निवेश

देश	अप्रैल 1996 से मार्च 2007	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	कुल
मॉरीशस	2572.1	1506.3	2651.2	2351.8	13106.9	7421.1	29609.3
सूडान	1144.8	8.3	64.9	6.9	13.9	0.001	1238.7
मिस्त्र	11.8	790.0	9.4	10.7	24.0	11.8	857.7
दक्षिण अफ्रीका	59.1	46.2	22.1	70.2	41.8	12.2	251.5
लीबिया	130.3	0.02	21.4	11.6	56.0	–	219.2
लाइबेरिया	155.2	17.7	18.0	–	–	0.4	191.4
केन्या	15.8	133.2	0.6	0.8	0.7	1.8	152.9
नाइजीरिया	36.4	27.2	1.4	1.4	8.9	16.3	91.6
मोरोक्को	32.5	0.4	2.3	0.7	38.0	0.0	74.0
गैबन	63.0	–	1.3	4.8	0.1	0.2	69.3
अन्य	73.8	36.3	35.4	63.2	56.4	46.3	311.5
अफ्रीका	**4294.8**	**2565.7**	**2827.9**	**2521.9**	**13346.7**	**7510.0**	**33067.0**
भारत के कुल में प्रतिशत हिस्सा	**13.7**	**11.1**	**16.5**	**14.0**	**30.4**	**24.3**	**20.1**

टिप्पणीः शून्य या उपलब्ध नहीं को इंगित करता है. एफडीआई आंकड़ों में इक्विटी, ऋण एवं जारी गारंटियां शामिल हैं.
स्रोतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक

अफ्रीका में एक्ज़िम बैंक

भारत सरकार की रणनीति के अनुरुप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, संवर्धन और उसे सुगम बनाने के लिए भारत की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण, सलाहकारी और सहायक कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला संचालित करता है. एक्ज़िम बैंक की वर्तमान में 4.9 बिलियन यूएस डॉलर की 114 ऋण–व्यवस्थाएं अफ्रीका के 48 देशों की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषक के लिए उपलब्ध हैं.

एक्ज़िम बैंक ने अफ्रीका में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रेषण लाइनें स्थापित करने, दूरसंचार नेटवर्क, बहु–उत्पाद पाइपलाइन, रोड, पावर स्टेशन, आईटी पार्क आदि में संविदाओं को निष्पादित करने वाले कई भारतीय परियोजना निर्यातकों को सहायता प्रदान की है. एक्ज़िम बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, तेल एव गैस खोज और फॉर्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भी कंपनियों को सहायता प्रदान की है. एक्ज़िम बैंक ने कारोबारी संबंधों को बढ़ाने और दक्षिण–दक्षिण व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने के लिए अफ्रीका की कई संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये हैं.

निर्यात विपणन सेवाएं
अक्तूबर–दिसम्बर 2012

हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल (डब्ल्यूसीसी) ने अक्तूबर 2012 में चेन्नै में अनेक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित कीं. डब्ल्यूसीसी की 17वीं महा सभा के अवसर पर 7–10 अक्तूबर, 2012 के दौरान छात्रों के लिए 'एक्ज़िम बैंक डब्ल्यूसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट फिल्म प्रतियोगिता' विषय पर एक क्राफ्ट फिल्म प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. इस कार्यक्रम का उद्देश्य परंपरागत क्राफ्ट के बारे में फिल्म डाक्यूमेंट्री आर्काइव बनाना और युवा छात्रों द्वारा उनके देश की परंपराओं को प्रदर्शित करना था. इस कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने किया. उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में श्री टी. सी. ए. रंगनाथन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक); सुश्री उषा कृष्णन, अध्यक्ष डब्ल्यूसीसी; डॉ. सैयद हमीद, योजना आयोग के सदस्य; सुश्री किरण बेंगरा; सचिव, वस्त्र और सुश्री कस्तूरी गुप्ता मेनन; अध्यक्ष, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल थे.

क्राफ्ट फिल्म प्रतियोगिता निम्नलिखित विषयों पर आयोजित की गई थी. जीवन संघर्ष, क्राफ्ट–सृजन के लिए जादू और क्राफ्ट–संस्कृति का मार्गपट्ट.

प्रतियोगिता में 26 देशों से 70 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं. पहले तीन पुरस्कार क्रमश: तिब्बत की सुश्री इयरीन दावाझान्भा को 'स्मान सोड घाटी में मिट्टी की मूर्तिकलाछवि' के लिए; टर्की की सुश्री नागिआन चकर को 'जिलान के रंग' के लिए तथा भारत की सुश्री नीला भास्कर को 'थोलू–बोमलता – चमड़े की कठपुतली कला' के लिए प्रदान किए गए.

इस दौरान अनेक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जिनका उद्देश्य मुख्यतः दुनिया के हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के साथ–साथ शिल्पकारों को मंच प्रदान करना और विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने एवं विपणन करने का अवसर प्रदान करना था.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महा प्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
मुंबई
फोन : (022) 22172713
ई–मेल : deepali@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस केन्द्र के कार्यकलाप
अक्तूबर–दिसम्बर 2012

एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय निर्यात संघ फेडरेशन (एफआईईओ) के सहयोग से 18 अक्तूबर को 'ईओयू और एसईजेड का रणनीतिक प्रबंध' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई. 19 नवम्बर को 'डब्ल्यूटीओ ढांचे के अंतर्गत डंपिंगरोधी करार तथा डंपिंगरोधी महा निदेशक की भूमिका एवं कर्तव्य' विषय पर कार्यशाला–सह–चर्चा सत्र रखा गया. 20 दिसम्बर को 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान शर्तों का रणनीतिक प्रबंधन' विषय पर भी एक कार्यशाला आयोजित की गई.

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने अर्जेन्टिना के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से 5 नवम्बर को 'अर्जेन्टिना में निवेश और व्यापार अवसर' तथा 17 दिसम्बर को 'अर्जेन्टिना के साथ व्यापार' पर दो संगोष्ठियां आयोजित कीं.

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने 23 नवम्बर को एफआईईओ तथा विश्वेश्वरया इंडस्ट्रियल ट्रेड सेन्टर के सहयोग से 'इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन प्रमाणपत्र और ड्यूटी ड्रॉबैक निदेशालय के बारे में भी एक कार्यशाला आयोजित की. इसके अलावा, वीआईटीसी के सहयोग से 30 नवम्बर को 'एक्ज़िम बैंक की योजनाएं एवं सेवाएं' तथा 10–15 दिसम्बर के दौरान 'निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर कार्यशाला आयोजित की गई.

एक्ज़िमिअस केन्द्र के आगामी कार्यक्रमों में चेन्नै में 'अर्जेन्टिना के साथ कारोबार'; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम व 'प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम'; 'अरब देशों के साथ कारोबार' पर संगोष्ठी; 'भारत द्वारा हस्ताक्षरित आरटीए. कर्नाटक राज्य के सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए उभरते कारोबारी अवसर' पर कार्यक्रम; वीआईटीसी और एफआईईओ के साथ संयुक्त रूप से माल क्षेत्र में 'कर्नाटक के निर्यातकों पर डब्ल्यूटीओ के प्रभाव' विषय पर संगोष्ठी शामिल हैं.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

श्री टी.वी. राव
सलाहकार, एक्ज़िमिअस केन्द्र
भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
बैंगलोर
फोन : (080) 25589106
ई–मेल : eximius@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा
इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी

'इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी : डिबंकिंग मिथ्स दैट अंडरमाइन प्रोग्रेस एंड एड्रेसिंग न्यू चैलेंजेज' पुस्तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जगदीश भगवती और डॉ. अरविंद पांगड़िया द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है. पुस्तक का शीर्षक 1947 में भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये भाषण से लिया गया है.

पुस्तक में विकास बनाम कल्याण वाद विवाद का समाधान किया गया है और इसका उद्देश्य सुधारों के बारे में नकारात्मक विचारों का प्रतिकार करना है. लेखकों ने ट्रैक–1 और ट्रैक–2 सुधारों को स्पष्ट किया है. प्रथम ट्रैक उन सुधारों से संबंधित है जिनका उद्देश्य राजस्व उत्पन्न कर विकास को बढ़ाना और उसे धारणीय बनाना जबकि दूसरा ट्रैक ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित है जो इस राजस्व को सबसे ज्यादा जरुरतमंद लोगों को वितरित करते हैं.

पुस्तक के तीन भाग और 17 अध्याय हैं. भाग–1 में कुछ प्रचलित मिथ्या धारणाओं को दूर किया गया है. आनुभविक रूप से समाधान की गई कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं: भारतीय नियोजनकर्ताओं ने पहले विकास को ही अपना लक्ष्य रखा था उन्होंने गरीबी मिटाने और अन्य सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की. स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक उद्देश्य के रूप में केवल हाल में विचार किया गया. चूंकि सत्तर के दशक तक गरीबी में कमी नहीं आई, अतः यह स्पष्ट हो गया कि अपनाई गई विकास रणनीति अनुपयुक्त थी. गरीबी मिटाने के लिए पुनर्वितरण आवश्यक है. भाग–2 ट्रैक 1 सुधारों का अधूरा एजेंडा है और इसमें श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण, बुनियादी संरचना और उच्च शिक्षा पर बल दिया गया है. भाग–3 सरकारी खर्च में सुधार के बारे में है.

लेखकों के अनुसार कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के धीमें प्रवाह के कारण भारत में आर्थिक विकास दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या ताइवान की तुलना में कम समावेशी हैं. तथा 'उद्योग विरोधी श्रम कानूनों के कारण कारोबार को बढ़ाने में कठिनाई होती है. पुस्तक में लेखक सारे श्रम कानूनों में सुधार अथवा उन्हें पुनः तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं.

देशों का सूक्ष्मावलोकन

इथियोपिया

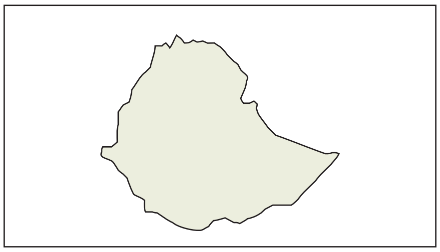

इथियोपिया वर्तमान में अफ़्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह सबसे तेज गति से विकसित होता गैर–तेल अफ़्रीकी देश है. अनुमान है कि 2012 में यह केन्या से आगे निकल कर पूर्वी अफ़्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. विश्व बैंक के अनुसार गत दशक में अफ़्रीकी क्षेत्र की तुलना में इथियोपिया की अर्थव्यवस्था दुगुनी दर से बढ़ी है, जिसका 2004 से 2011 के बीच वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) उप–सहारा अफ़्रीका के 5.2 प्रतिशत की तुलना में औसतन 10.5 प्रतिशत रहा. इथियोपिया ने अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर लगातार बढ़ती उच्च मुद्रास्फीति को रोकने में उल्लेखनीय प्रगति की है. वर्तमान में इथियोपिया ब्लू नाइल नदी पर स्थित रेनेसंस डैम पर अफ़्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्लांट लगा रहा है. 4.5 बिलियन यूस डॉलर की इस परियोजना से 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है. इस परियोजना को 2018 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है. दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश इथियोपिया कृषि पर अपनी निर्भरता को कम कर अपनी अर्थव्यवस्था का विशाखन कर रहा है. सरकार की पंचवर्षीय विकास योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इथियोपिया की जीडीपी का लगभग 16 प्रतिशत औद्योगिक विकास, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा एवं आवास पर निवेश करने की योजना है.

मोजाम्बिक

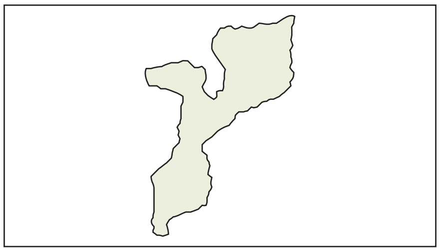

मोजाम्बिक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है. विदेशी निवेशक देश के अब तक न इस्तेमाल किये गये तेल और गैस भण्डार में रुचि दिखा रहे हैं. कोयला निर्यात से उत्साहित मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से विकसित हो रही है. आईएमएफ के अनुसार इसकी जीडीपी वृद्धि दर 2013 में 8.4 प्रतिशत होने की आशा है. मोजाम्बिक कमजोर होती वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के चलते लचीला बना रहा और दक्षिणी अफ़्रीकी क्षेत्र में इसकी मुद्रास्फीति दर सबसे कम रही. मोजाम्बिक के पास दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान कोयला खानें हैं. मोजाम्बिक सरकार देश से कोयले का निर्यात करने के लिए 2 बिलियन यूएस डॉलर बंदरगाह और रेल–रोड लाइन परियोजना पर खर्च करने का विचार कर रही है. हाल में दो बड़े गैस भण्डारों की खोज होने से यह ऊर्जा का आकर्षण केन्द्र बन गया है. मोजाम्बिक, रूस, ईरान और कतर के बाद अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश बन गया है.

यूएई

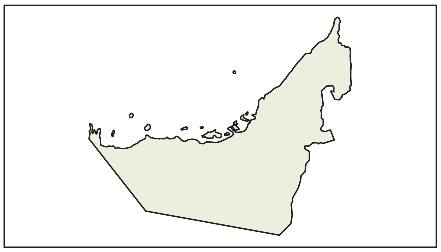

'दि नेशनल' द्वारा मिडल ईस्ट इन्वेस्टर रिलेशन्स सोसायटी के साथ किये गये सर्वेक्षण में यूएई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है तथा जीसीसी क्षेत्र में यह शीर्ष वित्तीय हब के रूप में उभरा है. 2011 में यूएई के पास दुनिया के प्रमाणित तेल भण्डार का लगभग 5.9 प्रतिशत था. अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल निर्यात है जो सरकार के विदेशी विनिमय और सरकारी राजस्व के लिए जबरदस्त आय उत्पन्न कर रहा है. यूएई ने आबूधाबी में हबशन फील्ड्स से लेकर ओमान की खाड़ी पर फुजैराह तक 400 किमी. लंबी पाइपलाइन बिछाई है जिसकी क्षमता एशियाई बाज़ारों को 2 मिलियन बैरल तेल प्रति दिन निर्यात करने की है. इसके कारण इसे अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों से बढ़त मिली है.

उरुग्वे

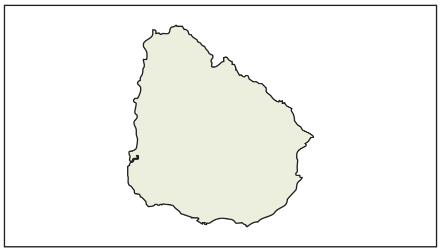

उरुग्वे में 2012 में मुख्यतः विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है. स्थानीय ब्याज दरों में वृद्धि और मूडीज तथा एस एण्ड पी द्वारा हाल में रेटिंग को बढ़ाकर निवेश श्रेणी करने से हाल में इसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है. उरुग्वे ने अल्पकालिक निवेश प्रवाह को रोकने के लिए अगस्त में पूंजी नियंत्रणों का उपयोग करने का निर्णय लिया तथा अपनी मुद्रा को और बढ़ने से रोका. इस घोषणा से उरुग्वे लैक क्षेत्र के देशों में से ब्राजील के साथ हो गया, जिसने अपनी स्थानीय मुद्रा को बढ़ने से रोकने के उपायों को अपनाया. मुद्रा में वृद्धि जो निर्यातों को अधिक महंगी करती है. उरुग्वे लैक क्षेत्र में विश्व बैंक के नये वित्तपोषण साधन, पी फॉर आर का उपयोग करने वाला भी पहला देश बन गया. यह कार्यक्रम सरकारी निवेश कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है. उम्मीद है कि वर्ष 2015 तक इस कार्यक्रम के जरिए पुलों, जल निकासी प्रणाली सहित लगभग 500 किमी सड़क का पुनर्मिमाण हो जाएगा तथा उरुग्वे राष्ट्रीय रोड नेटवर्क के 8,875 किमी के रोड चेतावनी संकेतक सुधार दिये जायेंगे.

वियतनाम

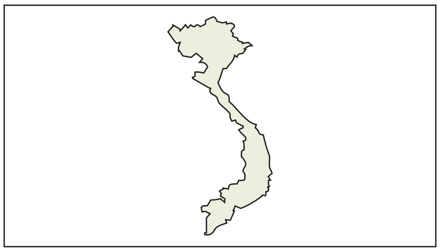

विश्व बैंक ने एशिया प्रशांत के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वियतनाम में प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. वियतनाम ने गरीबी मिटाने के लिए अपने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को पूरा कर लिया है. सरकार ने 2013 के लिए जीडीपी विकास दर और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अगले पांच वर्षों में इस देश के विनिर्माण क्षेत्र में 10 शीर्ष सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी देशों में से एक होने की उम्मीद है. वियतनाम सरकार ने हाल में अधिक लचीली नीतियां अपनाई हैं. यह क्षेत्रीय देशों के समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट आयकर में कमी करने और अपने कारोबारी माहौल में सुधार करने पर भी विचार कर रहा है.

रूस का रूबल

रूबल (आरयूबी) रूस तथा बेलारुस की मुद्रा है. यह कई अन्य देशों की मुद्रा इकाई भी थी जो सोवियत संघ से प्रभावित थे. रूबल को 1 जनवरी, 1998 को (1 नया आरयूबी=1000 पुराना आरयूबी के रूप में) पुनः मूल्यवर्गित किया गया.

रूस की जीडीपी विकास दर वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 2012 की पहली छमाही की 4.5 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2012 की तीसरी तिमाही में 2.9 प्रतिशत रह गई. वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 2013 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के 6–6.5 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है. उच्च ब्याज दर माहौल निवेश को प्रभावित कर रहा है. पूंजीगत खर्च के लिए कुछ समायोजनकारी राजकोषीय प्रोत्साहन अगले वर्ष आ सकते हैं. निजी क्षेत्र विदेश से उधार ले रहा है और तीसरी तिमाही में 26 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण से निवल पूंजीगत बहिर्वाह कम हुआ है. दिसम्बर में उच्च बाह्य ऋणों (22 बिलियन अमरीकी डॉलर) की चुकौतियां और बजट घाटे से रूबल के कमजोर होने की आशंका है. रूस के केन्द्रीय बैंक (सीबीआर) ने पुनर्वित्तपोषण की दर 8.25 प्रतिशत रखी है.

मध्य–पूर्व में सैनिक तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल के मूल्यों में उछाल से अमरीकी डॉलर की तुलना में रूबल मजबूत हुआ है. यूरोप में बाहरी मांग में कमी का प्रभाव रूस में आर्थिक मंदी के रूप में सामने आ रहा है. वास्तविक जीडीपी 2011 में 4.3 प्रतिशत होने के बाद 2012 में अभी भी लगभग 3.5 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ रही है. पारिवारिक वास्तविक आय में कमी के कारण अन्तर्निहित घरेलू मांग भी कमजोर हो रही है जिसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री की वृद्धि दर धीमी है. आकर्षक घरेलू निवेश अवसरों के अभाव में निवेश वृद्धि भी कमजोर है, इसके कारण 2012 में 67 बिलियन अमरीकी डॉलर का पूंजी बहिर्वाह होने का अनुमान है.

सीबीआर के मौद्रिक रूख में नरमी दिखाई दे रही है क्योंकि विकास धीमा हो गया है. हालांकि यह अभी भी विकास दर को अनुमान के करीब होने की आशा कर रहा है. वर्ष 2013 में सीबीआर मुद्रास्फीति में कमी कर इसको अक्तूबर 2012 के 6.5 प्रतिशत से पुनः 5.0–6.0 प्रतिशत की रेंज में रखना चाहता है. इन परिस्थितियों में रूबल आगे चलकर कमजोर होगा. 31 दिसम्बर, 2012 को अमरीकी डॉलर की तुलना में रूबल 30.5277 पर उद्धृत हो रहा था.

ब्राजील का रियल

ब्राजिलियन रियल (बीआरएल) दुनिया की कुछ उन मुद्राओं में से एक है जिस पर अर्थशास्त्री अति उत्सुकता से नजर रखते हैं. 18 जनवरी, 1999 से रियल अमरीकी डॉलर के समक्ष मुक्त रूप से फ्लोट हो रहा है. बीआरएल मुख्यतः ब्राजील की घरेलू नीतियों पर निर्भर करती है. उच्च प्रतिफल देने वाले ब्राजील जैसे देश निवेशकों को आकर्षित करते हैं. अत: इस क्षेत्र में जोखिम होने के बावजूद गत पूरे वर्ष ब्राजील में अत्यधिक पूंजी अंतर्वाह हुआ. ब्राजील बीआरएल में सतत वृद्धि के कारण इसकी मजबूती के लिए भी चिंतित है औ हस्तक्षेप कर सकता है.

रियल में जून 2012 से सर्वाधिक वृद्धि हुई है क्योंकि आर्थिक विकास में सहायता के लिए पूंजी नहीं थी जिससे वृद्धि काफी कम रही. यह विश्लेषकों द्वारा तीसरी तिमाही में लगाये गये अनुमान से आधी से थी. मुद्रा में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और प्रति अमरीकी डॉलर 2.0879 हो गई, यह 29 जून, 2012 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी. 25 उभरते बाज़ारों की मुद्राओं में रियल में वृद्धि सर्वाधिक हुई. रियल में सर्वाधिक वृद्धि तब हुई जब केन्द्रीय बैंक के एक अधिकारी ने एक साक्षात्कार में कहा कि नीति निर्माताओं ने मुद्रा में गिरावट को गंभीरता से लिया है.

सरकार विनिमय–दर बाज़ार में लिक्विडिटी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है. नीति निर्माता इस बात पर कायम हैं कि रियल उस स्तर तक कमजोर हो गई है जो देश की आर्थिक बुनियादी संरचना के अनुरूप नहीं है. ब्राजील के नीति निर्माताओं ने रियल में गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप किया. सांख्यिकी एजेंसी द्वारा 30 नवम्बर, 2012 को सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में तीसरी तिमाही में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि रिपार्ट की गई, जो अर्थशास्त्रियों के मध्यकालिक पूर्वानुमान 1.9 से कम है इसके बाद मुद्रा में गिरावट आई.

अक्तूबर में 0.25 बिन्दु की कमी के बाद बान्को सेन्ट्रल डो ब्रासिल (बीसीबी) ने एसईएलआईसी लक्ष्य दर को 7.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. 31 दिसम्बर, 2012 को अमरीकी डॉलर की तुलना में बीआरएल 2.0488 पर उद्धृत हो रहा था.

चीनी युआन

चीन ने 1979 से दोहरी विनिमय दर नीति अपना रखी थी. 1994 में युआन को स्थिर करने के लिए इसने एकीकृत दर अपनाई. इससे युआन को एशियाई वित्तीय संकट तक 8.28 प्रति अमरीकी डॉलर से 8.30 प्रति अमरीकी डॉलर की परिधि में ऊपर नीचे होने की अनुमति दी और इसके बाद यह वस्तुतः 8.28 प्रति अमरीकी डॉलर पर स्थिर रही. चीन ने स्थिर दर व्यवस्था से अस्थिर दर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 21 जुलाई, 2005 को अपनी मुद्रा को पुनर्मूल्यांकन कर 8.11 प्रति अमरीकी डॉलर कर दिया. इस व्यवस्था के अंतर्गत पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) युआन को केन्द्रीय बैंक की मध्य दर का पुनर्निर्धारण पूर्व दिन के बंद मूल्य से 0.30 प्रतिशत प्रतिदिन (मई 2007 में और बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया) बढ़ने और कम होने की अनुमति प्रदान करता है.

तटीय और अपतटीय रेनमिन्बी बाज़ार नवम्बर 2012 में अधिकांश स्थिर रहे क्योंकि पीबीओसी ने हस्तक्षेप नहीं किया. लेकिन केन्द्रीय बैंक यह कहता रहा है कि अमरीकी डॉलर/चीनी युआन की लगभग 6.30 विनिमय दर दीर्घकालीक है. इसलिए यदि पीबीओसी हस्तक्षेप नहीं भी करे तो यह अपने भरोसे के आधार पर बाजार को ट्रेडिंग में लाने का प्रयास कर रहा है. लेकिन यदि दीर्घकाल में यह धारणा गलत निकलती है तो यह हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं हो पायेगा. बाजार अनुमानो के अनुसार अगले वर्ष के अंत तक पीबीओसी कुछ आंतरिक व्यवस्था करने के लिए हस्तक्षेप करेगा. बाज़ार यह मानता है कि पीबीओसी वर्ष की ऐसी समाप्ति से संतुष्ट नहीं होगा जिसमें सभी प्रकार के ऑफरों वाले माहौल में स्पॉट 1 प्रतिशत के सुदृढ़ अवरोध पर हो और कोई बोली न हो (जिसकी दुष्क्रियाशील बाज़ार से तुलना हो सकती है). इसलिए यह हस्तक्षेप या अर्ध–हस्तक्षेप के द्वारा तत्काल दर को उठाने की कार्रवाई करेगा.

बाज़ार उम्मीद करता है कि पहली तीन तिमाहियों में दर बहुत ही धीमी गति (0.5 पाइंट प्रति तिमाही) से कम (रेनमिन्बी के मजबूत) होगी, जिसमें स्पॉट दर लगभग 1 प्रतिशत के आसपास रहेगी इसके बाद 2013 की चौथी तिमाही में बैंड +/– 2 प्रतिशत होगा जिससे स्पॉट दर 2 प्रतिशत के नये स्तर पर पहुंचेगी अगले 12 महीने में अमरीकी डॉलर/चीनी युआन विनिमय दर का पूर्वानुमान 6.0500 है. 31 दिसम्बर, 2012 को अमरीकी डॉलर की तुलना में चीनी युआन 6.2313 पर उद्धृत हो रहा था.

एक दशक में सेज से निर्यात में 40 गुना वृद्धि

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के सृजन का उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एकल खिड़की (सिंगल विंडो) अनुमोदन एवं न्यूनतम विनियमनों के साथ बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर व और आकर्षक छूट/सहायता प्रदान कर आर्थिक विकास को बढ़ाना था. भारत में पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ईपीजेड) 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था, इसके बाद 7 और क्षेत्र स्थापित किये गये. अप्रैल 2000 में ईपीजेड मॉडल में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सेज नीति की घोषणा की गई. सेज नीति के कार्यान्वयन से सभी मौजूदा ईपीजेड सेज में परिवर्तित हो गये.

निवेशकों में विश्वास जगाने सेज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने तथा सेज की स्थापना के जरिये आर्थिक विकास व रोजगार पैदा करने के लिए व्यापक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया तथा 23 जून, 2005 से लागू हुआ. सेज नियम 10 फरवरी, 2006 से लागू हुए. इस प्रकार प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया और केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित मामलों में एकल खिड़की अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था की गई. सेज अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है. भारत में 380 सेज हैं जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और परिचालन के विभिन्न चरणों में हैं इनमें से 154 सेज निर्यात के लिए हैं. निर्यातवाले सेजों में 88 सेज आईटी/आईटी समर्थित सेवा क्षेत्र के हैं, इसके बाद बहु–उत्पाद (17 सेज), इंजीनियरिंग (9 सेज) और फार्मास्यूटिकल्स एवं रसायन (8 सेज), वस्त्र एवं परिधान (ऊन सहित), खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, बॉयो–टेक, गैर–परंपरागत ऊर्जा, हस्तशिल्प आदि शामिल हैं.

भारत का निर्यात बढ़ाने में सेज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. गत दशक में सेज से निर्यात 2001–02 में 9,200.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 2011–12 में 364,477.7 करोड़ रुपये हो गया **(तालिका)**. 2011–12 में सेज से निर्यात 15.4 प्रतिशत बढ़कर गत वर्ष के 315,867.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 364,477.7 करोड़ रुपये हो गया.

वर्ष 2010–11 (अद्यतन आंकड़ों के अनुसार) सेज से निर्यात में रसायन फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा हिस्सा 33.7 प्रतिशत रहा, इसके बाद कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर (26.8 प्रतिशत), रत्न एवं आभूषण (15.1 प्रतिशत), ट्रेडिंग एवं सेवा (11.4 प्रतिशत) और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर (6.7 प्रतिशत) का स्थान रहा. अन्य क्षेत्रों यथा इंजीनियरिंग, वस्त्र एवं परिधान, गैर–परंपरागत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक एवं रबड़, बॉयोटेक, चमड़ा, जूते एवं खेलकूद का सामान, खाद्य एवं कृषि उद्योग तथा हस्तशिल्प का मामूली हिस्सा रहा.

तालिकाः भारत में कार्यरत एसईजेड से निर्यात

वर्ष	एसईजेड से निर्यात	
	₹ '000 करोड़	प्रतिशत वृद्धि
2001–02	9.2	8.9
2002–03	10.1	9.3
2003–04	13.8	37.4
2004–05	18.7	35.0
2005–06	22.8	22.4
2006–07	34.8	52.3
2007–08	66.6	91.6
2008–09	99.7	49.6
2009–10	220.7	121.4
2010–11	315.9	43.1
2011–12	364.5	15.4

स्रोतः इंडियास्टैट, एमओसीआई, भारत सरकार से लिये गये.

भौगोलिक फैलाव के आधार पर वर्ष 2010–11 में भारत के कुल सेज निर्यात में गुजरात का हिस्सा 46.5 प्रतिशत रहा, इसके बाद कर्नाटक (14.8 प्रतिशत), तमिल नाडु (13.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (6.3 प्रतिशत), केरल (5.9 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (4.2 प्रतिशत) का स्थान रहा.

वर्ष 2010–11 में मौजूदा सेजों में से कुछ प्रमुख निर्यात निष्पादकों में रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लि., गुजरात (बहु–उत्पाद सेज), तमिल नाडु में नोकिया विशेष आर्थिक क्षेत्र (टेलीकॉम उपकरण सेज), महिन्द्रा सिटी सेज, तमिल नाडु (परिधान एवं फैशन वस्तुएं, आईटी/हार्डवेयर, ऑटो सहायक उपकरण) और विप्रो लि., कर्नाटक–2 सरजापुर में 2 सेज और इलेक्ट्रॉनिक सिटी (आईटी सेज) शामिल हैं.

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इन तमाम वर्षों में सेज निर्यात में अच्छी खासी वृद्धि हुई है. किन्तु सेज निर्यात पांच क्षेत्रों में ही केन्द्रित है (रसायन फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर/ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, रत्न एवं आभूषण, ट्रेडिंग एवं सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर) जिनका कुल सेज निर्यात में 94 प्रतिशत हिस्सा है, के भौगोलिक फैलाव की दृष्टि से गुजरात, कर्नाटक और तमिल नाडु से कुल सेज निर्यात का 75 प्रतिशत हिस्सा रहा.

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं. प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है.

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है –
1 करोड़ : 10 मिलियन
1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.
दूरभाष : 91 – 22 – 2217 2600
फैक्स : 91 – 22 – 2218 2572
ई–मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in